Ok"ki % 40(vad % 09 (flrEcj % 2018(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

5 सितम्बर, 2018 : संसद के समक्ष

ऐतिहासिक मजदूर किसान संघर्ष रैली

रैली को संबोधित करते हुए

(ऊपर) **सी.आई.टी.यू. महासचिव तपन सेन**

(नीचे) **ए.आई.के.एस. महासचिव हन्नान मोल्ला**

मुंशी प्रेम चंद

भारतीय साहित्य के वरिष्ठ एवं अगुआ मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन की 136वीं सालगिरह 31 जुलाई को थी

मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता पर फासीवादी हमले के खिलाफ प्रतिरोध

सीटू देश के विभिन्न हिस्सों में 28 अगस्त को दलितों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गैरकानूनी छापेमारी और गैरकानूनी क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तारियों की निंदा करता है। सीटू ने 29 अगस्त को एक बयान में कहा कि असहमति किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, और यह उसका दमन करने का एक स्पष्ट प्रयास है।

सीटू 30 अगस्त को नई दिल्ली में संसद मार्ग पर इस फासीवादी और सत्तावादी हमले के खिलाफ जन एकता जन अधिकार आंदोलन (जेईजेएए) की तत्काल विरोध रैली में एक प्रमुख घटक के रूप में, शामिल हुआ। महासचिव समेत इसके केंद्र के सभी सीटू पदाधिकारियों ने इस विरोध कार्रवाही में भाग लिया।

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

सीटू मजदूर

lhvkbVh;w dk e[ki=

सितम्बर 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,
एम एल मलकोटिया,
कश्मीर सिंह ठाकुर,
पुष्पेन्द्र त्यागी,
एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

5 flrEcj l?k"kZ jSyh 5
etnwj&fdlku xBcU/ku &riu lu 6
9 vxLr fdlku&etnwj tu Hkkjr &d- geyrk 9
tu Hkkjr l?k"kZ &v'kksd /koyr 11
lkefgd tkxj.k & d- geyrk 17
dqjy fot;h gksxk &,-d- iùukHku 20
m|ksx o {ks= 22
jkT;ksa ls 24
miHkksDrk eY; lwpdkad 26

सम्पादकीय

एक आखिरी धक्का और दो दमन का राज तोड़ दो

समूची मेहनतकश जनता तितरफा हमले के निशाने पर है; नवउदारवाद हमलावर हुआ; फूटपरस्त फासिस्टी रास्ते के रुझान बढ़ रहे हैं; और भाजपा की केंद्र तथा राज्य की तानाशाह हुयी जा रही सरकारें नागरिक स्वतंत्रताओं और मानवाधिकारों को अलोकतांत्रिक तरीके से कुचलने पर आमादा हैं। यही वह समय है जब हमारी आर्थिक और सामाजिक जिंदगी में साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ और उसकी घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है।

इस तरह के चौतरफा हमलों का सामना करते हुए भारत के जनवादी आंदोलन ने अपने आपको भी एक बहुआयामी उच्चस्तर पर पहुंचाया है। मजदूर, किसान और खेत मजदूरों के बुनियादी वर्ग देशव्यापी साझी कार्यवाहियों के लिए साथ आ रहे हैं: क्षेत्रीय, उद्योग आधारित तथा सभी मजदूरों की हड़तालों सहित संयुक्त आम कार्यवाही करके केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और फेडेरेशने संघर्ष को और ऊंचाई प्रदान कर रही हैं: और इसी के साथ सौ से ज्यादा वर्गीय संगठन, जनसंगठन एवं सामाजिक संगठन एकजुट होकर एक मंच से व्यापक जनतांत्रिक सवालों को उठा रहे हैं।

इसी 2018 के साल में सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन ने मिलकर 19 जनवरी का दिन, 1982 की पहली आम हड़ताल के शहीदों की स्मृति के दिवस के रूप में मनाया; 9 अगस्त को देश भर में जेल भरो आंदोलन किया; और 5 सितम्बर को संसद के समक्ष विराट अखिल भारतीय मजदूर किसान संघर्ष रैली की। एडवा ने 4 सितंबर को संसद के समक्ष महिलाओं की रैली आयोजित की।

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक फेडरेशनों ने 9 से 11 नवम्बर के दिल्ली के तीन दिवसीय महापड़ाव के बाद जनवरी में जिला स्तरीय सत्याग्रहों का सफल आयोजन किया: फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ 2 अप्रैल को केरल में साझी हड़ताल और देश भर में विरोध दिवस की कार्यवाहियां हुईं: 28 सितम्बर को एक साझा राष्ट्रीय कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसका मुख्य एजेंडा अगले साल की पहली तिमाही में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का फैसला करने का है। किसान संगठन 28–30 नवंबर को संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 100 किमी लंबे मार्च को आयोजित करने जा रहे हैं। डीवाईएफआई युवाओं के प्रतिरोध मार्च को आयोजित करने जा रही है।

वर्गीय संगठन, जनसंगठन एवं सामाजिक संगठनों के जन एकता जन अधिकार आंदोलन के साझा मंच ने 23 मई को जिला तथा स्थानीय स्तर की रैलियों का आयोजन किया था: गौरी लंकेश की हत्या और नागरिक तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ विरोध कार्यवाहियां हुई।

आततायी जुल्मी सरकार और उसके विरुद्ध लड़ने वाले लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोई संदेह नहीं कि जनता के जीवन और जीवन दशाओं पर हमले और उनके नतीजे में उनकी तकलीफें जारी हैं; मगर इसी के साथ जनता का जुझारू प्रतिरोध और इन्हें धक्का मारकर उलटने की जिद भी बढ़ रही है। यही आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में इस सरकार को निर्णायक धक्का देकर उसे हटाने तक जायेगा: यहीं भर रुकेगा नहीं, नीतियों के जनहितैशी बदलाव और नए भारत के निर्माण तक जारी रहेगा।

बुद्धिजीवियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा एक अपील

5 सितंबर की मजदूर–किसान रैली को सफल बनाओ

मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों की 5 सितंबर की रैली देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना होगी। अब तक देश में मजदूरों या किसानों या खेत मजदूरों की अलग–अलग रैलियाँ होती रही हैं, लेकिन इन सभी तबकों की संयुक्त रैली कभी नहीं, निश्चित रूप से राजधानी में तो इस पैमाने पर नहीं। यह पहला ऐसा प्रयास होगा।

इन वर्गों का साथ आना केवल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परियोजना नहीं है। नव–उदारवाद के तहत उनकी आर्थिक नियति निकटता से जुड़ी हुई है। नव उदारवाद द्वारा कृषि से राज्य का समर्थन वापस लेने के माध्यम से उभरता कृषि संकट, जिसने आत्महत्याओं के द्वारा पिछले दो दशकों के दौरान तीन लाख से अधिक जानों को निगल लिया है। और इसी के चलते अनेक लोगों को ग्रामीण इलाकों से बाहर, शहरी क्षेत्रों में नौकरियों की तलाश के लिए मजबूर किया है। ऐसी नौकरियों अस्तित्व में न होने के कारण, उन्होंने बेरोजगारी और बेरोजगार मजदूरों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी कर दी है और इस तरह शहरी मजदूरों के सभी हिस्सों यहाँ तक कि संगठित और यूनियनों में शामिल मजदूरों की वास्तविक मजदूरी और काम की परिस्थितियों को खराब करने में अनजाने में योगदान दिया है।

नव–उदारवाद के साझा पीड़ित सभी वर्गों का गठबंधन, नव उदारवादी व्यवस्था को काबू करने का प्राथमिक साधन है। इसलिए उस संयोजन का भी सामना करने के लिए प्राथमिक साधन है जो वर्तमान में देश पर शासन करने वाले सांप्रदायिक–सत्तावाद की ताकतों को बनाए रखता है। यह गठबंधन इस भयावह प्रवृत्ति की अंतिम हार का साधन है।

इस गठबंधन को स्वरुप लेने के लिए, नव उदारवाद ने उसमें उद्देश्य क्षमता बनाई, जो इस गठबंधन में है, जो चेतनशील होकर परिवर्तन के लिए प्रमुख की भूमिका निभाने लगता है, उसके लिए 5 सितंबर की रैली एक महत्वपूर्ण कदम है। हम उन सभी लोगों से अपील करते हैं जो इस रैली में शामिल होने के लिए जाति, सांप्रदायिक और लिंग आधारित प्रणाली पर शोषण और भेदभाव से मुक्त भारत बनाने में रुचि रखते हैं, जो एक नई शुरुआत को चिह्नित करते हैं, और हर संभव तरीके से इसका समर्थन करने, संलग्नक दस्तावेज में सूचीबद्ध इन वर्गों की माँगों को तत्काल समर्थन करने को तैयार हैं।

जारीकर्ता

प्रभात पटनायक, के. सच्चिदानंदन, विवान सुंदरम, एमके रैना, राम रहमान, मदनगोपाल सिंह, वेंकटेश रामकृष्णन, एनके शर्मा, एमएमपी सिंह, सोहेल हाश्मी, पीके शुक्ला, डीएन झा, अर्जुन देव, लता सिंह, सीपी चंद्रशेखर, जोया हसन, गौहर रजा, दिनेश अब्रोल, जयति घोष, उत्सा पटनायक, राजेन्द्र प्रसाद, सुराजित मजुमदार, अर्चना प्रसाद, प्रबीर पुरकायस्थ, सुबोध वर्मा, मलयश्री हाशमी, काजल घोष, डी.रघुनन्दन, अमित सेनगुप्ता, इन्द्राणी मजुमदार, सुधन्वा देशपांडे, विजय प्रसाद।

सीटू-किसान सभा-खेत मजदूर यूनियन का संयुक्त आह्वान

5 सितम्बर 2018 को मजदूर किसान संघर्ष रैली

सीटू, किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन ने 5 सितंबर 2018 को संसद के समक्ष 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संयुक्त रैली आयोजित की जा रही है।

एकजुट हों! संघर्ष करो – • कॉरपोरेट समर्थक, भूस्वामी समर्थक सरकारों के खिलाफ • मजदूर–विरोधी, किसान–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी नीतियों के खिलाफ; • उन नीतियों के लिए जो सभी मेहनतकशों को लाभ पहुंचाती हैं;

मुख्य माँगें – 1. मूल्य वृद्धि पर रोक लगाओ; सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली; आवश्यक वस्तुओं में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाओ; 2. सम्मानजनक रोजगार पैदा करने के लिए ठोस उपाय लागू करें; 3. सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 18000 रुपये प्रति माह से कम नहीं; 4. श्रम कानूनों में मजदूर–विरोधी संशोधन वापस लिए जाऐं; 5. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करें; और समय पर सार्वजनिक खरीद हो; 6. गरीब किसानों और खेत मजदूरों को ऋणों में माफी लागू की जाए; 7. खेत मजदूरों के लिए व्यापक केंद्रीय कानून पारित करें; 8. सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा लागू करें और शहरी क्षेत्रों को कवर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करें; 9. सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सुनिश्चित करें; 10. सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें; 11. रोजगार में ठेकाकरण नहीं हो, और पुरुषों और महिलाओं को एक समान काम के लिए समान वेतन लागू हो; 12. पुर्नवितरणशील भूमि सुधारों को लागू किया जाऐ; 13. जबरन जमीन अधिग्रहण बंद करो; 14. प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास प्रदान करें; और 15. नवउदार नीतियों को उलट दें।

ऐतिहासिक मजदूर-किसान संघर्ष रैली

संसद के सामने; 5 सितम्बर, 2018

सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा व अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के संयुक्त आह्वान; देशव्यापी अभियान; तथा 9 अगस्त की संयुक्त जेल भरो कार्रवाई के बाद लाखों मजदूर,किसान व खेतमजदूर देश के सभी भागों से; लगभग सभी राज्यों व केन्द्र शाषित प्रदेशों से; बारिश के बावजूद,बाढ़ व अन्य मुश्किलों का सामना करते हुए; हर तरह के आवागमन के साधनों का उपयोग कर, संसद के सामने हुई ऐतिहासिक मजदूर–किसान संघर्ष रैली में शामिल होकर,मजदूरों,किसानों,खेतमजदूरों,बेरोजगार युवाओं व जनता के अधिकारों व जरुरतों से संबंधित 15 सूत्रीय माँगपत्र को देने के साथ ही मोदी सरकार को यह स्पष्ट संदेश देने दिल्ली आ पहुँचे कि जनता का बढ़ता गुस्सा इस आक्रमक नवउदारवादी नीतियों व विभाजनकारी एजेंडें वाली सरकार को उखाड़ कर ही शांत होगा। ये सभी भारत की जनता के लिए एक नये भारत के संघर्ष को आगे बढ़ाने पहुँचे थे।

भारी संख्या में महिला व पुरुष दिल्ली के रामलीला मैदान स्थित मुख्य शिविर तथा कई अन्य शिविरों में 3 सितम्बर से ही पहुँचने शुरु हो गये थे। उन्होंने पूरी नम्रमा के साथ,उस असुविधा का सामना किया जो स्वागत समिति तथा वालंटियरों के द्वारा रहने की न्यूनतम जरुरतें प्रदान करने की हर संभव कोशिशों के बावजूद बारिश के कारण तरबतर कैंपों में उन्हें हुई थी। बड़े ही धैर्य के साथ वे बारिश में रामलीला मैदान से शुरु होने वाले जुलूस के लिए कतारबद्ध खड़े रहे। रामलीला मैदान से शुरु हुए मार्च में तीनों संगठनों के नेतागण सबसे आगे थे। उनके बाद तीनों संगठनों के लाल शर्ट वाले वालंटियर थे। जैसे–जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,पड़ौसी राज्यों के जत्थों के साथ ही साहिबाबाद में लगे एक अन्य कैम्प व आठ अन्य जगहों पर जमा हुए जत्थे मुख्य जुलूस में शामिल होते गये रैली और बड़ी होती गई।

मार्च के 10 बजे संसद मार्ग पर लगाये गये पुलिस अवरोधों के सामने पहुँचते ही वह रैली व एक विशाल जनसभा में बदल गया। रैली में जमा लोगों की भारी संख्या जहाँ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से लगाकर कनाटप्लेस के इनर सर्किल तक फैली थी वहीं वह आस–पास के जंतर–मंतर रोड व अन्य सड़कों व लेनों तक फैली थी। जुलूस व रैली के कारण नई दिल्ली का सड़क परिवहन घंटों तक अस्त–व्यस्त रहा और संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप्प रहा।

जनसभा की अध्यक्षता ,तीनों संगठनों के अध्यक्षों वाले अध्यक्षमंडल ने की। स्वागत समिति के चेयरमैन प्रो. प्रभात पटनायक तथा तीनों संगठनों में से प्रत्यके की ओर से 10 राष्ट्रीय नेता मंच पर मौजूद थे। सभा को सीटू की अध्यक्ष के. हेमलता, ए आइ के एस के अध्यक्ष अशोक धवले ए आइ ए डब्ल्यू यू के अध्यक्ष थिरुनावक्कारासु; सीटू महासचिव तपन सेन, ए आइ के एस महासचिव हन्नान मोल्ला तथा ए आइ ए डब्लयू के महासचिव विजयाराघवन; सीटू से संबद्ध व एसोसिएटिड 17 फेडरेशनों के नेताओं; किसान सभा के 12 अन्य नेताओं व खेतमजदूरो के 4 अन्य नेताओं; तथा स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता ने संबोधित किया। किसान सभा के अमराराम खेतमजदूर के बृजलाल भारती व सीटू के तपन सेन ने समापन भाषण दिया।

खराब मौसम के बावजूद,रैली में शामिल होने वालों में पूरा जोश था, वे अपनी माँगों व मुद्दों को उठाने व सरकार जनविरोधी तथा विनाशकारी एजेंडें का भंडाफोड़ करने वाले नेताओं के भाषणों का नारे लगाकर व तालियां बजाकर प्रत्युत्तर दे रहे थे। कारपोरेट मीडिया ने इस बार अपनी रिपोर्टों में अपने जीवंत अनुभवों को सामने रखने वाले आम मजदूरों,किसानों व खेतमजदूरों के व्यक्तिगत साक्षात्कारों को सम्मान के साथ दर्ज किया।

रैली ने, तीनों संगठनों के द्वारा आने वाले समय में किये जाने वाले आन्दोलनों में एक दूसरे के साथ एकजुटता कार्रवाईयां करने का संकल्प लिया; इन आन्दोलनों में सैंकड़ों किसान संगठनों द्वारा नई दिल्ली की ओर किया जाने वाला 3 दिवसीय 100 किलोमीटर का लॉंग मार्च; केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों के द्वारा संयुक्त रुप से की जाने वाली प्रस्तावित मजदूरों की 2 दिवसीय आम हड़ताल तथा दिल्ली में डी वाई एफ आई की युवा रैली शामिल हैं।

etnj fdlku l?k"k jyh dk vkoku

मजदूर किसान गठबंधन को आगे ले जाना है

तपन सेन, महासचिव सीटू

सीटू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू के नेतृत्व में 5 सितंबर 2018 को संसद के समक्ष ऐतिहासिक और विशाल 'मजदूर किसान संघर्ष रैली'; देशव्यापी अभियान, लामबन्दी और आंदोलनों की पहले से जारी श्रृंखला का अगला हिस्सा थी। अब, केंद्र में सरकार की मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष ने एक नया चरण पूरी तरह से एक नया आयाम दर्ज किया है। तैयारियों के प्रारंभिक दौर से ही आह्वान को हासिल करते हुए, मजदूरों, किसानों और खेत मजदूरों में उत्साहजनक प्रतिक्रिया के चलते, धुर दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम तक देश के हर हिस्से से, 5 सितंबर की रैली में भारी भागीदारी गर्मजोशी से स्वागत का संकेत है कि मजदूर वर्ग द्वारा अपने मुख्य वर्ग सहयोगी, खेत मजदूरों और किसानों का नवउदारवादी व्यवस्था के खिलाफ संगठित प्रतिरोध का ही एक लक्षण है।

यह देश के जनवादी आंदोलन के इतिहास में पहली बार है कि मजदूरों किसानों की इस तरह की संयुक्त कार्रवाहियों जिले के Lrj vkSj gkrd कि कई राज्यों में तो निम्न स्तर तक भी, आयोजित की जा सकी हैं जिनका समापन विशाल राष्ट्रीय रैली में हुआ है। भारत में आजादी के बाद, मजदूरों, खेत मजदूरों और किसानों, जो राष्ट्र की धन–दौलत के असली निर्माता हैं, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पहिये चलाने के अलावा, राष्ट्रीय राजकोष में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रमुख योगदानकर्ता हैं। देश को आगे बढ़ने में उनकी केंद्रीय भूमिका ऐसी है कि यदि वे एक साथ काम करना बंद कर दें, तो सब कुछ ढ़ह जाएगा। मजदूरों और किसानों के वर्गीय गठबंधन की मजबूती से शोषण की संकटग्रस्त प्रणाली से लड़ने का पूरे मेहनतकश वर्ग को एहसास हो जाएगा और अपनी अंतर्निहित क्षमता और ताकत को खोजकर मेहनतकश वर्ग के पक्ष में व्यवस्था को पलट देगा।

मजदूरों–किसानों के गठबंधन के इस नए आयाम को निरंतरता के साथ मजबूती से और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में देश की मेहनतकश जनता की विशाल रैली द्वारा बड़ी सहज प्रतिक्रिया से हमें दी गई यही दिशा है।

पिछले कई सालों से संयुक्त अभियान और आंदोलन बनाने के प्रयास चल रहे हैं। सीटू ने बाल विकास की एक व्यापक योजना के निजीकरण और अंततः समाप्ति के खिलाफ, और 'आईसीडीएस बचाओ' के लिए एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू के साथ संयुक्त अभियान के लिए पहल की है। किसानों और खेत मजदूरों को शामिल करने के प्रयास किए गए थे जो इस योजना के लाभार्थियों और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को जो इसे जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। बिजली विधेयक के मुद्दे पर भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे।

पिछले तीन सालों से, सीटू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू संयुक्त रूप से 19 जनवरी को षहीद दिवस के रूप में हर साल मनाते आ रहे हैं, उस दिन 1982 में आजादी के बाद पहली संयुक्त देशव्यापी हड़ताल के दौरान मजदूरों, खेत मजदूरों और किसानों सहित 10 लोगों की पुलिस गोलीबारी में मौत हो गयी थी। इस हड़ताल की माँगों में किसानों के लिए लाभकारी मूल्य और खेत मजदूरों के लिए व्यापक कानून आदि किसानों और खेत मजदूरों की प्रमुख मांगें शामिल थीं।

इसके अलावा, संयुक्त ट्रेड़ यूनियन आंदोलन ने एआईकेएस और अन्य किसान संगठनों द्वारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और इसके बाद भाजपानीत मोदी सरकार के संबंधित विधेयक के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष को सक्रिय एकजुटता और समर्थन दिया। संयुक्त ट्रेड़ यूनियन आंदोलन ने अपने सभी आंदोलनों और संघर्षों में अध्यादेश और विधेयक का विरोध किया। दृढ़ एकजुटता वाले किसानों के मजबूत विरोध और मजदूर वर्ग के आंदोलन ने अंततः मोदी सरकार को अध्यादेश को समाप्त होने देने और विधेयक को फौरी तौर पर दफ्न करने के लिए मजबूर किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण छूट आदि जैसी अन्य माँगों पर किसानों के संघर्षों को ट्रेड यूनियन आंदोलन का समर्थन और एकजुटता भी मिली।

इस तरह की संयुक्त कार्रवाहियों की पहलों को वर्तमान वर्ष में एक नई गति मिली है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में पुलिस दमन का सामना करने वाले किसानों के संघर्ष और नासिक से मुंबई तक उनके लाँग मार्च आदि ने देश भर में मजदूरों को प्रेरित किया है। विशाल देशव्यापी आम हड़तालों और मजदूरों के अद्वितीय तीन दिवसीय 'महापडाव' ने किसानों को उत्साहित किया।

मार्च 2018 में आयोजित सीटू जनरल काउंसिल ने 9 अगस्त 2018 को देशव्यापी जेल भरो के लिए एआईकेएस के आह्वान का स्वागत किया और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलकार पूरे देश में कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया। एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू ने 5 सितंबर 2018 को संसद पर भारी मार्च आयोजित करने के लिए सीटू की पहल का स्वागत किया और इसमें शामिल होने के लिए तैयार होकर इसे एक मजदूर किसान संघर्ष रैली बना दिया।

संयुक्त आह्वान से उत्पन्न उत्साह, देश भर में 393 जिलों में कम से कम 540 स्थानों में 9 अगस्त 2018 को जेल भरो में पांच लाख से अधिक किसानों और मजदूरों की भारी भागीदारी में दिखायी दिया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, 14 अगस्त 2018 को रात भर के 'सामूहिक जागरण' कार्यक्रम में भी यह प्रतिबिंबित हुआ था, जिसमें 39,000 स्थानों पर 62,000 से अधिक मजदूरों और उनके परिवारों ने शिरकत की थी; कई स्थानों पर किसान भी कार्यक्रम में शामिल हो गए। इसके अलावा, तीनों संगठन जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीति व्यवस्था का पर्दाफाश करने के लिए कई राज्यों में जमीनी के स्तर पर चलाऐ गऐ अभियान में एक साथ शामिल हुए।

ये संयुक्त गतिविधियां और अभियान, अपने अधिकारों और रहने की स्थितियों की रक्षा के लिए नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी एकजुट संघर्ष के लिए मेहनतकशों की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। इन नीतियों के उलटे जाने और जन–समर्थक नीति व्यवस्था लाने के उद्देश्य से जुझारु संयुक्त संघर्षों के विकास का वे वादे करते हैं। इसे संघर्ष जारी रखने और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के निरंतर प्रयासों के माध्यम से हासिल किया जाना है।

मजदूरों–किसानों के गठबंधन के निरंतरता के साथ संयुक्त संघर्ष को जारी रखने का दृढ़ संकल्प, अपने शुरुआती चरण से ही, लड़ाई के मैदान में संबद्धताओं के ऊपर उठकर आम जनता के अन्य वर्गों के संगठनों को आकर्षित करने, देश भर में संघर्ष के माहौल को तब्दील करना शुरू कर दिया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों का एकजुट मंच पहले से ही दशकों से नवउदारवादी नीति व्यवस्था के खिलाफ कई हड़ताल कार्रवाइयों सहित कई आंदोलन आयोजित कर रहा है और उस प्रक्रिया में देश के लगभग सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों को संघर्ष के संयुक्त एकता मंच में आकर्षित करने के लिए लगातार कोशिश की गयी है। इस पृष्ठभूमि में, मजदूरों किसानों के गठबंधन की पहल ने समाज के विभिन्न हिस्सों के जीवन और जीविका पर जन–विरोधी नीतियों के गंभीर असर के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई करके, जनसंख्या के बड़े हिस्से की बेचेनी और क्रोध की जोरदार अभिव्यक्ति की है।

डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में जिला मुख्यालय में केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के समक्ष दिनभर धरना और इसके बाद 3 नवंबर 2018 को संसद के समक्ष लगभग 50,000 युवाओं की एक बड़ी रैली आयोजित का फैसला किया है। ये कार्यक्रम सरकार की रोजगार की हत्या की नीतियों और रोजगार सृजन पर इसकी धोखाधड़ी के अभियान का पर्दाफाश करेंगे।

अखिल भारतीय किसान संयुक्त संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएसएससीसी) जिसमें देश के किसानों और खेत मजदूरों के विभिन्न संगठन शामिल हैं, ने दिल्ली के आसपास के 7/8 स्थानों से 100 किलोमीटर लंबे संसद मार्च का आयोजन करने का फैसला किया है जिसमें देश के सभी हिस्सों से किसान और खेत मजदूर भाग लेंगे।

राज्य और केंद्र सरकारों के, प्रतिरक्षा निर्माण, बैंकों और बीमा, दूरसंचार और अर्थव्यवस्था के लगभग सभी रणनीतिक क्षेत्रों के कर्मचारियों, कोयले, इस्पात, आदि में सभी प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के लगभग सभी राष्ट्रीय स्वतंत्र फेडरेशनों, बिजली, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और गोदी, सड़क परिवहन, आदि के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों और इसके घृणास्पद मंसूबों के खिलाफ, कार्यस्थल के स्तर पर अभियान चलाने का फैसला किया है। श्रम कानूनों में नियोक्ता–समर्थक बदलावों के माध्यम से कामकाजी लोगों पर गुलामी थोपने के खिलाफ, वर्ष के अंत में दो दिन की देशव्यापी आम हड़ताल की जाएगी। 28 सितंबर 2018 को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में आयोजित मजदूरों के राष्ट्रीय कन्वेंशन में देशव्यापी आम हड़ताल सहित कार्रवाहियों के कार्यक्रमों का विवरण तैयार किया जाएगा। उपरोक्त के अलावा, अनेक क्षेत्रीय संघर्ष भी निकट भविष्य में होने हैं।

हम केंद्र की एक चरम दक्षिणपंथी–प्रतिक्रियावादी सरकार की नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हर क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मेहनतकश जनता के जीवन और आजीविका पर सबसे ज्यादा हमलों की अगुआई कर रही है। यह सबसे

जघन्य राजनीतिक गिरोह है जो जनता की एकता को कमजोर और खण्डित करके, सांप्रदायिक और विभाजक ध्रुवीकरण को विकसित करने के लिए अपनी शासकीय रणनीति के एक हिस्से के रूप में एक जहरीला अभियान चला रही है। हम एक विषैले और साथ ही साथ एक सत्तावादी संगठन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो अपने नियंत्रण के तहत राज्य मशीनरी का उपयोग करके, अहमति और मुक्त अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रहा है जो लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। ये सभी नवउदार पूंजीवादी राज की रणनीति का अभिन्न अंग हैं और इसका प्रतिचालक शासन गहन संकट, जो इसे पूरी तरह निगल चुका है, के दौर में खुद को बनाए रखने में उलझा हुआ है।

हमारे संघर्ष को नवनिवेशवादी पूंजीवादी व्यवस्था और सत्ता पर आसीन चरम दक्षिणपंथी निजाम द्वारा समाज पर जहरीले षड़यंत्रों के खिलाफ व्यापक रूप से निर्देषित होना है। मजदूरों–किसानों के गठबंधन के इस संघर्ष में निश्चित रूप से पूरी तरह से मजदूर वर्ग की एकता को बढ़ाना और संघर्ष के हर चरण में इस गठबंधन को मजबूत और विस्तारित करते जाना, हमारे समक्ष महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए वर्गीय ट्रेड़ यूनियन आंदोलन की अधिक सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है ताकि किसानों और खेत मजदूरों के संगठनों के संघर्ष और गतिविधियों के हर चरण में एकजुटता की कार्रवाई के साथ सक्रिय रूप से शामिल हो सके, चाहे वह स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर हों। यह गठबंधन दृढ़ निरंतरता के साथ पूंजीवादी व्यवस्था और नवउदारवाद की राजनीति के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थिर मंच की कार्रवाई में इस गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए मजदूर वर्ग के आंदोलन की मुख्य जिम्मेदारी है। 9 अगस्त के जेल भरो और 5 सितंबर की मजदूर किसान संघर्ष रैली की भारी सफलता ने हमें आत्मविश्वास दिया है और हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए शस्त्र–सज्जित किया है। पूरे सीटू को इस आत्मविष्वास से लबरेज करें।

हम होंगे कामयाब!

राज्यों से

तेलंगाना के बिजली ठेका मजदूरों की सफल हड़ताल

ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे टी ई टी यू एफ के नेतृत्व में 5 दिसम्बर 2016 के आंदोलन के उपरान्त मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रुप से राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में लगे सभी 23,663 ठेका मजदूरों को नियमित करने का वादा किया था। सीटू से संबद्ध यूनाइटेड इलैक्ट्रिसिटी एम्लाईज यूनियन पॉवर सैक्टर के आऊटसोर्स कर्मचारियों, आर्टिजन्स की माँगों को उठाती रही है। तथापि, एक स्वतंत्र यूनियन ने इन ठेका मजदूरों की माँगों को लेकर 21 जुलाई से हड़ताल का नोटिस दिया। सीटू यूनियन ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई और 24 अगस्त को विशाल विद्युत सौध घेरा डालो कर जिससे 3,500 से ज्यादा बिजली मजदूर शामिल थे, हड़ताल में शामिल हो गई।

जे ए सी के हड़ताल में शामिल हो जाने पर सरकार व प्रबंधन दबाव में आ गये। पॉवर मिनिस्टर तथा ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड (टी एस ट्रांसको) ने हड़ताल से बाहर रही 4 यूनियनों समेत सभी पाँच मान्यताप्राप्त यूनियनों के साथ त्वारित परामर्श किया और उसी दिन 28 जुलाई को आर्टीजंस कहे जाने वाले ठेका मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी को लागू करने का आदेश जारी कर दिया; तथा मान्यताप्राप्त हड़ताली व गैर–हड़ताली यूनियनों ने हड़ताल समाप्त कर दी। जे ए सी ने भी हड़ताल वापस ले ली व 31 जुलाई से और भी तेज आंदोलन करने का ऐलान किया। टी एस ट्रांसको के सी एंड एम डी तथा सरकार के विशेष मुख्य सचिव ने 30 जुलाई को जे ए सी को लिखे प़ में आदेश के लागू होने की प्रति के साथ माँगे माने जाने की सूचना देते हुए प्रस्तावित आंदोलन न करने की अपील की।

आदेश को लागू करने की सूचना में प्रबंधन ने तुरंत ही उच्च न्यायालय ठेका मजदूरों को नियमित कर्मचारी बनाये जाने पर लगे स्थगनादेश को हटाने के लिए हलफनामा दाखिल करने; कुल पारिश्रमिक बढ़ाने–बढ़े वेतन व विशेष भत्ते के साथ 1 अगस्त 2018 को ग्रेड IV के लिए 19,548 रुपये, ग्रेड 3 के लिए 21,719 रुपये, ग्रेड 2 के लिए 25,042 रुपये तथा ग्रेड 1 आर्टिजंस के लिए 29,743 रुपये करने; ई पी एफ व ई एस आइ में नियोक्ता के अंशदान को अतिरिक्त लाभ बनाने; मृतक कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी; ग्रेड 4 व ग्रेड 3 के कुशल कार्य करने वाले आर्टीजंस को ग्रेड 2 का पारिश्रमिक देने; ड्यूटी पर दुर्घटना के लिए मेडिकल क्रेडिट कार्ड आदि देने पर सहमति दी। कुछ अन्य माँगों का परीक्षण किया जायेगा।

(योगदानः सुधाभास्कर रुपनगुंटे)

9 अगस्त किसान–मजदूर 'जेल भरो'

कई तौर पर महत्वपूर्ण

d- geyrk v/;{k lhVw

दशकों में पहली बार, हमारे देश की संपत्ति बनाने वाले, मेहनतकशों के दो प्रमुख तबके मजदूर और किसान सरकार की नीतियों के खिलाफ जुझारु कार्रवाइयों में शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) के द्वारा गिरफ्तारी देने के आह्वान को सीटू द्वारा समर्थन किया गया था, जिसमें मजूदरों को इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा गया था।

सीटू केंद्र को प्राप्त शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, कार्यक्रम 22 राज्यों में 393 जिलों में 539 स्थानों पर आयोजित किया गया था। कुछ अन्य लोगों के साथ किसानों, मजदूरों और खेत मजदूरों के बुनियादी तबकों से कुल 4,43,417 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। इनमें से 2,08,103, लगभग 47% मजदूर थे। किसानों की माँगों के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की भागीदारी उत्साहजनक है। वास्तव में, 22 राज्यों में से 10 राज्यों – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, मध्यप्रदेश, पंजाब और तेलंगाना आदि में मजदूरों की भागीदारी 60% से अधिक होने की सूचना मिली है जबकि तीन राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के मजदूरों की भागीदारी कुल प्रतिभागियों के आधे से अधिक की रही थी। केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में मजदूरों की भागीदारी 30% और 40% के बीच थी। हालांकि, 3 अन्य राज्यों त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मजदूरों की भागीदारी 30% से कम थी। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई जगहों पर पुलिस को गिरफ्तार करने की पेशकश करने वाले सभी को गिरफ्तार करने की आवश्यक मशीनरी नहीं थी।

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सत्तारूढ़ दलों, क्रमशः टीएमसी और बीजेपी द्वारा अपने राज्यों में धमकियों और शारीरिक हमलों के द्वारा डराने के बावजूद भी किसानों और मजदूरों की विशाल एवं जुझारु भागीदारी ने, पूरे देश में लोगों को प्रेरित किया। इन राज्यों में पुलिस ने प्रतिभागियों के खिलाफ आंसू गैस, पानी की तोप, लाठी चार्ज इत्यादि का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल में, गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों को दूसरे दिन की शाम तक भी छोड़ा नहीं गया था। इन दोनों राज्यों में जेल भरो में किसानों और मजदूरों की बहादुरी पूर्ण भागीदारी ने देश भर के लोगों के बीच विश्वास पैदा किया कि इस तरह के संघर्षों को जारी रखकर और मजबूत करके इन राज्यों में वामपंथी अपनी जगह हासिल कर पाएंगे और प्रमुख ताकत के रूप में उभरेंगे, जो परिणाम स्वरुप नवउदारवादी शासन के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष को बढ़ावा देगा।

किसानों की माँगों के समर्थन में, देश के कई हिस्सों में महिला मजदूरों की बड़ी संख्या में भागीदारी एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। कई जिलों में, उन्होंने न केवल भाग लिया बल्कि प्रदर्शनों का आयोजन करने में पहल की और गिरफ्तारी के कार्यक्रम का नेतृत्व किया। हालांकि कार्यक्रम में मजदूरों के विभिन्न हिस्सों की भागीदारी के बारे में जिलेवार विवरण का इंतजार है, यहाँ तक कि गुजरात जैसे राज्य में, जहाँ सीटू कमजोर है, तीन जिलों में, जहाँ न तो सीटू से संबद्ध अन्य कोई यूनियन है और ना ही किसान सभा मौजूद है, वहाँ आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आशाओं ने अपनी यूनियनों के बैनर के तहत प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। पंजाब में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और कई जिलों में गिरफ्तारी दी।

मजदूरों के बीच उत्साह दर्शनीय था जो 9 अगस्त के अदालती गिरफ्तारी के कार्यक्रम में बड़ी भागीदारी के रुप में दिखा और देश के आधे से अधिक जिलों में फैल गया था। यह मजदूर किसान गठबंधन की स्थापना के लिए आगे बढ़ते मजदूरों और किसानों के संयुक्त अभियानों और संघर्षों को तेज करने और मजबूत बनाने की क्षमता को इंगित करता है। अकेला ऐसा गठबंधन ही निर्णायक रूप से हमारे देश की मेहनतकश जनता पर नवउदारवादी हमलों को परास्त कर सकता है।

न सिर्फ मजदूरों के बल्कि मजदूरों और किसानों के व्यापक संयुक्त संघर्षों को विकसित करने की आवश्यकता के मद्देनजर, नवउदारवादी नीतियों को उलटने के उद्देश्य से, उनके खिलाफ आक्रामक संघर्ष शुरू करने पर कई वर्षों से सीटू द्वारा जोर दिया जाता रहा है। किसानों की माँगों एवं संघर्षों और शोषित और उत्पीड़ित जनता के अन्य वर्गों के समर्थन और एकजुटता को बढ़ाकर मजदूरों की राजनीतिक चेतना विकसित करने के एक उपाय के रूप में देखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त अभियान विकसित करने के प्रयास किए गए थे। सीटू, ए.आई.के.एस. और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू.) ने कुछ साझा माँगों को लेकर 19 जनवरी को एक साथ मनाने का संयुक्त आह्वान किया था। 9 अगस्त को गिरफ्तारी का कार्यक्रम इस

तरह की संयुक्त कार्रवाहियों को उँचे स्तर पर लेकर गया है और संयुक्त संघर्षों को विस्तारित और समेकित करने के अवसर खोले हैं।

'जेल भरो' कार्यक्रम की सफलता, भाजपानीत मोदी सरकार द्वारा आक्रामक रूप से अपनायी गयी नवउदारवादी नीतियों के प्रभाव के खिलाफ मेहनतकश जनता के बढ़ते असंतोश और गुस्से को दर्शाती है। इस समय क्या करने की जरूरत है कि जनता के इस असंतोष और गुस्से को नवउदारवादी शासन के खिलाफ संघर्ष के उच्चतर रूपों में विस्तारित करना है। किसानों और मजदूरों को अपने रोजमर्रा के मुद्दों और शासक वर्गों द्वारा अपनायी जा रहीं नवउदारवादी नीतियों के बीच के संबंध और वैकल्पिक नीतियों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। जब तक उनकी वर्गीय चेतना विकसित नहीं की जाती है, तब तक सत्तारूढ़ वर्ग उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे और उनकी रोजमर्रा की वास्तविक समस्याओं से उनका ध्यान, गोमांस खाने, गाय संरक्षण, लव जिहाद आदि जैसे बनावटी मुद्दों की ओर हटाते रहेंगे। चुनाव के वास्ते, आरएसएस और बीजेपी सहित इसके संगठन, अपनी नीतियों की विफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, सांप्रदायिक और विभाजनकारी मुद्दों की ओर मोड़ने के लिए अपनी सभी चालों और अपने कब्जे के सभी संसाधनों का सख्ती से उपयोग करेंगे। वे लोगों की एकता को छिन्न–भिन्न करने और सांप्रदायिक और जाति के आधार पर समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए सभी तौर–तरीकों का उपयोग करेंगे। किसानों और मजदूरों के रोजमर्रा एवं आजीविका के मुद्दों पर और नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ाई को, सभी रंग–रुपों की, विशेष रूप से आरएसएस, जिसका केंद्र और कई राज्यों में भाजपा की सत्ता के साथ बड़ा और व्यापक प्रभाव रखने वाली सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों के विभाजनकारी और विघटनकारी एजेंडा के खिलाफ लड़ाई के साथ जोड़ा जाना है। जनता की एकता की रक्षा के लिए सभी प्रयास किए जाने हैं।

सीटू ने मजदूरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इस अवधि के दौरान प्रयास किए हैं कि हमारे देश के साथ–साथ वैश्विक स्तर पर शासक वर्ग, जनता की एकता को छिन्न–भिन्न करने और नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ उनके संघर्षों को कमजोर करने के लिए दक्षिणपंथी ताकतों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहें हैं। इसने किसानों की स्थितियों के बारे में मजदूर वर्ग के बीच जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है और कि पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से लगातार सरकारों द्वारा द्वारा अपनायी गयी नवउदारवादी नीतियों के कारण गरीब और सीमांत किसानों और खेत मजदूरों को कैसे–कैसे भुगतना पड़ा है। सीटू केंद्र द्वारा तैयार की गई अभियान सामग्री में न्यूनतम समर्थन मूल्य, खेत मजदूरों और ग्रामीण संकट के कारण प्रवासन पर 'चर्चा के बिंदु' सहित शामिल है, जिसका मकसद यूनियन कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना है। हालांकि, कृषि संकट और ग्रामीण संकट से संबंधित कुछ और सामग्री को परिकल्पित नहीं किया जा सका है।

मार्च 2018 में कोझिकोड में सम्पन्न सीटू जनरल काउंसिल द्वारा लिए गए फैसले में कि समूचे संगठन को पुर्नगठित करते हुए, अभियान की पहल के इस अभ्यास को अंततः 5 सितंबर 2018 के आंदोलन में भारी लामबन्दी के साथ समापन करना प्रभावी साबित हुआ है। सीटू जनरल काउंसिल ने सभी राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है, इसके बाद जिला और राज्यस्तरीय यूनियनों की कार्यशालाओं और सीटू से सम्बद्ध सभी यूनियनों की निम्नतम स्तर समितियों की बैठकों में दोनों मुद्दों पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। इनका उद्देश्य संगठन की जनवादी कार्यप्रणाली में सुधार करना, 'पहुँच से बाहर तक पहुँचना' और मुद्दों को नीतियों के साथ जोड़ना और नीतियों के पीछे राजनीति का पर्दाफाश करने को अभ्यास में लाना। मौजूदा गंभीर परिस्थिति के कारण जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कुछ अपरिहार्य कारणों से इसे केरल में स्थगित कर दिया था और अब सितंबर के उत्तरार्ध में आयोजित की जाऐंगी। कुछ राज्यों में जिला स्तर और राज्यस्तरीय यूनियनों की कार्यशालाएं भी पूरी की गई हैं। इन सभी कार्यशालाओं में 9 अगस्त 'जेल भरो' कार्यक्रम का महत्व समझाया गया था। इस प्रकार, निचले स्तर तक संगठनात्मक तैयारी और पहलों के परिणामस्वरूप मजदूरों की बड़ी भागीदारी हुई है।

सीटू के अनुभव से पता चलता है कि जनवादी कार्यप्रणाली में सुधार करके संगठन के सभी स्तरों पर सदस्यों को सक्रिय करने के लिए निरंतर प्रयास, और नवउदारवादी नीतियों को परास्त करने की आवष्यकता, मेहनतकश जनता के बड़े तबकों को सक्षम बनाने की आवश्यकता को समझने के लिए अपनी राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए जरूरी है। आज दश्ष को नियंत्रित करने वाली, मजदूर–विरोधी, किसान–विरोधी, जन–विरोधी सत्ता को परास्त करने का कोई छोटा रास्ता नहीं हो सकता है।

बेमिसाल देशव्यापी जेल भरो संघर्ष

v'kkd /koy

v/;{k] vf[ky Hkkjrh; fdlku lHkk

हाल के दिनों में देश भर में यह जेल भरो संघर्ष सबसे बड़ा था। राज्यों से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, 9 अगस्त, 2018 को देश भर के 23 राज्यों में 407 जिलों में 610 से अधिक केंद्रों में पांच लाख से अधिक किसानों और मजदूरों ने गिरफ्तारियां दी। उनका केंद्रीय नारा था ''मोदी सरकार, चले जाओ!''

यह इस तथ्य की मान्यता के साथ था कि नरेंद्र मोदी नीत भाजपा–आरएसएस सरकार, स्वतंत्र भारत के पिछले 71 वर्षों में सबसे ज्यादा किसान–विरोधी, मजदूर–विरोधी और जन–विरोधी है इसमें संदेह नहीं है। यह सबसे अधिक कॉरपोरेट–समर्थक, सांप्रदायिक और जातिवादी भी है।

किसानों, मजदूरों और खेत मजदूरों के इस जेल भरो संघर्ष का नेतृत्व एआईकेएस, सीटू और एआईएडब्ल्यूयूयू ने संयुक्त रूप से किया था। कुल मिलाकर, एआईकेएस के नेतृत्व में किसान लगभग तीन लाख थे और सीटू के नेतृत्व में मजदूर लगभग दो लाख थे। एआईएडब्ल्यूयू ने भी कुछ राज्यों में आंदोलन किया। इस कार्रवाई की सफलता के लिए गहन और व्यापक तैयारी सभी राज्यों में की गई थी।

मजदूर–किसान एकता को कार्रवाई में उतारने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था – एक और कदम जो दिल्ली में 5 सितंबर को मजदूर किसान संघर्ष रैली के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। एडवा, डीवाईएफआई और एसएफआई के नेतृत्व में महिलाओं, युवाओं और छात्रों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रधान मंत्री को संबोधित एआईकेएस की किसान माँगों पर प्रत्येक राज्य में लाखों हस्ताक्षर जिला अधिकारियों को सौंपे गए थे।

9 अगस्त को जेल भरो की हलचल ने जनता पर एक बड़ा प्रभाव डाला है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साथ ही साथ सोशल मीडिया दोनों ने क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष को अच्छी तरह से कवर किया। इस कार्रवाई ने किसानों और मजदूर वर्ग के संयुक्त प्रतिरोध को आगे बढ़ाने में मदद की।

राज्यवार तस्वीर

इस संघर्ष में सबसे बड़ा और सबसे जुझारु आंदोलन पश्चिम बंगाल में था, जहाँ 1,42,000 से अधिक लोगों ने राज्य के सभी जिलों में भाग लिया था। कई जगहों पर, हजारों प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से सत्तावादी टीएमसी सरकार द्वारा स्थापित कई बाधाओं को तोड़ दिया। पूर्व एआईकेएस के संयुक्त सचिव सूर्यकांत मिश्रा और कई अन्य लोगों के नेतृत्व में, उन्होंने पुलिस दमन का बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन झुकने से इंकार कर दिया। उन्होंने मोदी शासन के साथ–साथ ममता शासन दोनों को जन–विरोधी नीतियों के लिए फटकार लगायी।

त्रिपुरा में एक और बहादुराना संघर्ष हुआ, जहाँ वामपंथियों को, भाजपा–आरएसएस–आईपीएफटी के नेतृत्व में बर्बर शासन के भारी दमन का सामना करना पड़ रहा है। इस छोटे से राज्य में, जेल भरो की कार्रवाही में 11,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार और कई अन्य लोगों के नेतृत्व में, उन्होंने लाठी चार्ज और यहाँ तक कि पानी की तोपों एवं आंसू गैस आदि का भी बहादुरी से सामना किया।

केरल को खुद प्रकृति से ही एक अलग तरह के विरोध का सामना करना पड़ा! 9 अगस्त अभूतपूर्व बारिश का दिन था जो अंततः केरल में आपदाजनक बाढ़ का कारण बन गया। इस पर भी जीत दर्ज करते हुए जेल भरो कार्रवाही में 30,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अगर यह प्रचंड बारिश नहीं होती, तो यह आंकड़ा आसानी से कुछ लाख तक पहुंच जाता।

तमिलनाडु को पूरी तरह से अलग समस्या का सामना करना पड़ा – पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मौत। शोक अवधि के कारण, जेल भरो को रद्द करना पड़ा। उस दिन राज्य ने एक लाख से अधिक गिरफ्तारियों की योजना बनाई थी।

अन्य राज्यों में महाराष्ट्र के 27 जिलों में 66 केंद्रों में 63,437 की सबसे बड़ी भागीदारी थी। यहाँ आंदोलन एक लाख के लक्ष्य को पार कर गया होगा, यह उसी दिन मराठा जाति के आरक्षण के मुद्दे पर राज्य बंद का आह्वान न होता। अगला सबसे बड़ा बिहार था, जहां 50,000 से अधिक लोगों ने 35 जिला केंद्रों में भाग लिया था।

अन्य राज्यों में आंदोलन के आंकड़े निम्नानुसार थेः असम–35,000, पंजाब–35,000, राजस्थान–28,000, कर्नाटक–27,756, उत्तर प्रदेश–25,000, ओडिशा–23,500, आंध्र प्रदेश–13,000, तेलंगाना–12,336, हिमाचल प्रदेश–11,000, हरियाणा–11,000, झारखंड–8,496, मध्यप्रदेश–5,250, छत्तीसगढ़–3,370, गुजरात–3,174, उत्तराखंड–2,000, जम्मू–कश्मीर–1,900, दिल्ली–50, मणिपुर–50।

जेल भरो के लिए संकल्पना और तैयारी

दिल्ली में 18–19 मार्च, 2018 को आयोजित एआईकेएस केंद्रीय किसान समिति (सीकेसी) की बैठक ने किसानों की ज्वलंत माँगों को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने का फैसला किया और लोगों से 10 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करके, 9 अगस्त, 2018 को देष भर में जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर जेल भरो संघर्श करके समापन करने का निर्णय किया। 9 अगस्त, 1942 हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक तारीख है, जिस दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिष साम्राज्यवादी सरकार को 'भारत छोड़ो' की चेतावनी दी।

एआईकेएस द्वारा तय की गई मुख्य माँगों में भूमि अधिकार, जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन, कृषि ऋण में छूट, स्वामिनाथन आयोग के फॉर्मूला सी2+50% के अनुसार लाभकारी मूल्य, खेत मजदूरों और गरीब किसानों के लिए पेंशन में वृद्धि और एक व्यापक फसल बीमा योजना।

24–26 मार्च, 2018 को केरल के कोझिकोड में आयोजित सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक ने 9 अगस्त को जेल भरो संघर्ष में किसानों के साथ एकजुटता में भाग लेने का फैसला किया। सीटू ने प्रस्तावित किया कि इसके बाद 5 सितंबर, 2018 को दिल्ली में आजादी के बाद पहली बार मजदूर–किसान संघर्ष रैली का आयोजन किया जाएगा। एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू ने पूरी तरह से इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रकार यह सभी तीन वर्गीय संगठनों की संयुक्त रैली बन गया है।

18–20 जुलाई, 2018 को तमिलनाडु के राजपालयम में आयोजित एआईकेएस की अखिल भारतीय किसान परिषद (एआईकेसी) की बैठक ने जेल भरो और दिल्ली रैली की तैयारी की समीक्षा की और इन दोनों संघर्शों को एक बड़ी सफलता बनाने का एक स्पष्ट आह्वान किया। इसने देश भर में गांव के परिवारों और छोटे व्यापारियों प्रत्येक से 10 रुपये के अनुसार बड़े पैमाने पर संग्रह के माध्यम से मुख्य रूप से किसान संघर्ष फंड के रूप में 5 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया।

तीनों संगठनों के पदाधिकारियों के बीच बैठकें और परामर्श आयोजित किए गए। बुकलेट, हैंडबिल, वाहन या साइकिल जत्थों, सम्मेलनों और गांव की बैठकों के माध्यम से अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए पूरे देष में एक विशाल अभियान शुरू किया गया था।

9 अगस्त के संघर्ष में दो नए वर्ग भी शामिल हो गए। एक अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन, जो कि 'वन रैंक वन पेंशन' की उनकी जायज और लंबित मांग पर भाजपा सरकार द्वारा ठगे जाने से गुस्से में था। दूसरा अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा था जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रोकथाम अधिनियम को कम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दूर करने के लिए सरकारी निष्क्रियता से परेशान था। इसने पहले 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें पुलिस गोलीबारी में कई दलितों की मौत हो गई थी। हाल ही में संसद द्वारा पारित बिलों के माध्यम से यह मुद्दा सुलझा लिया गया है।

(अशोक ढवले के लेख से)

केरल की जनता के साथ डब्लूएफटीयू की एकजुटता

सीटू के राष्ट्रीय सचिव और डब्लूएफटीयू के उपमहासचिव एस देव रॉय, को लिखे एक पत्र में डब्लूएफटीयू के महासचिव जॉर्ज मावरिकोस ने लिखा, ''मैं केरल कीं स्थिति और त्रासदी को बारीकी से देख रहा हूँ''... हम इस प्राकृतिक विनाश के लिए बहुत दुख महसूस करते हैं जिसने क्षेत्र में सैकड़ों लोगों का जीवन छीन लिया है और केरल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में तबाही और भारत के हमारे साथी मजदूर वर्ग के दैनिक जीवन में इतनी आपदाएं और समस्याएं पैदा कर दी हैं।'' ''ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपके देश में होनी है, पूरे विश्व से ऊर्जा और रसायनों के क्षेत्र के ट्रेड यूनियन नेताओं का शामिल होना, इस पल में विशेष रूप से केरल के लिए एक प्रमुख महत्व की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की एक घटना होगी। ''डब्लूएफटीयू प्रतीकात्मक रूप से 5,000 अमरीकी डालर की राशि का योगदान देगा।

9 अगस्त, 2018 जेल भरो आंदोलन

पश्चिम बंगाल

त्रिपुरा

असम

ओड़ीशा

झारखंड

छत्तीसगढ़

9 अगस्त, 2018 जेल भरो आंदोलन

उत्तर प्रदेश

उत्तराखंड

हरियाणा

राजस्थान

पंजाब

9 अगस्त, 2018 जेल भरो आंदोलन

केरल

महाराष्ट्र

आन्ध्र प्रदेश

कर्नाटक

14-15 अगस्त, 2018 सामूहिक जागरण

कर्नाटक

तेलंगाना

पंजाब

राजस्थान

'सामूहिक जागरण'

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर

के. हेमलता अध्यक्ष, सीटू

सीटू ने पहली बार 14 अगस्त 2018 की रात्रि को पूरे देश में एकसामूहिक जागरण आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया। यह हजारों मजदूरों, किसानों और आम लोगों द्वारा किए गए बलिदानों को याद रखने के लिए था जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता के संघर्ष में अत्यधिक त्याग किए और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति को पुनःसमर्पित था।

हमारी स्वतंत्रता एक व्यक्ति या एक पार्टी के प्रयासों के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई थी। देष के मेहनतकशों, मजदूर वर्ग, किसानों, आदिवासियों आदि देश के कई हिस्सों में संघर्ष में सबसे आगे थे। आर्थिक शोषण और सामंती उत्पीड़न के खिलाफ अपने संघर्षों के साथ–साथ उन्होंने औपनिवेशिक शासन भी लड़ाई की जो इस तरह के शोषण और उत्पीड़न को मजबूत कर रहा था। उन्होंने अपने सभी कामों, अपनी कमाई, अपने परिवारों और अपने जीवन का बलिदान किया, इस विश्वास के साथ कि एक स्वतंत्र भारत औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न से मुक्त होगा। जिसमें निरक्षरता, गरीबी, तमाम तरह की असमानताऐं, बेरोजगारी और किसी भी तरह के उत्पीड़न को दूर करके बड़ी प्रगति होगी। एक ऐसा भारत जहाँ सभी नागरिकों को जाति, पंथ, धर्म या लिंग के बावजूद समान अधिकार और अवसर होंगे। सोवियत संघ ने उनकी आंखों के समक्ष समाजवादी व्यवस्था के तहत बड़ी प्रगति की थी। युवाओं ने भगत सिंह एवं उनके हथियारबन्द साथियों और सभी प्रगतिशील वर्गों के प्रतीक के रुप में स्वीकार किया जिन्होंने भारत में इसी तरह के समाज के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।

लेकिन स्वतंत्रता के बाद शासक वर्गों ने विकास का जो मार्ग चुना वह उनकी सभी उम्मीदों के खिलाफ रहा है। नवउदारवाद के आगमन ने मसलों को और भी खराब कर दिया है। यहाँ तक कि हासिल किए छोटे फायदों और जीते गए अधिकारों को भी मेहनतकश जनता से छीना जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के उभार ने हमारे देश की एकता और लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

इस प्रकार आज, मजदूर वर्ग और मेहनतकशों के सभी तबकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अपने पूर्वजों की दृष्टि को याद रखें और उनके सपनों को साकार करने के लिए लड़ाई जारी रखने के प्रति वचनबद्ध हो जाऐं।

इसी उद्देश्य के लिए सीटू जनरल काउंसिल ने 14–15 अगस्त की रात को पूरे देश में सामूहिक जागरण करने का फैसला किया था। यह नोट किया है कि पिछले कुछ वर्षों से सीटू की कर्नाटक राज्य समिति द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को किया जा रहा था, विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के युवा मजदूरों और योजना मजदूरों में अच्छी प्रतिक्रिया पैदा हुई थी।

मजदूरों के अलावा, बुद्धिजीवियों, कलाकारों और प्रगतिशील लोगों जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था और संदेश को ले जाने के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शन सहित विभिन्न गतिविधियों को भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवहार्यता पर कई सीटू राज्य समितियों के नेतृत्व में प्रारंभिक हिचकिचाहट थी, लेकिन जनरल काउंसिल के फैसले को लागू करने के प्रयास किए गए थे।

अब तक प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, 17 राज्यों में 234 से अधिक जिलों में सामूहिक जागरण 388 से अधिक केंद्रों – मुख्य रूप से राज्य/जिला/तालुक/मंडल मुख्यालयों में आयोजित किया गया था। कई केंद्रों में सामूहिक जागरण पूरी रात आयोजित किया गया था, कुछ केंद्रों में यह आधी रात तक समाप्त हुआ था। कुल 44,200 लोग, उनमें से अधिकतर युवा मजदूरों ने इसमें भाग लिया।

जम्मू–कश्मीर, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और केरल में गंभीर बाढ़ की स्थिति के कारण और गवर्नर की मौत के कारण छत्तीसगढ़ में यह नहीं हो सका।

आंध्र प्रदेश में, सामूहिक जागरण 19 जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया था। सैकड़ों मजदूरों ने अपने परिवारों के साथ भाग लिया। सभी केंद्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि कुछ में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और पुरस्कार वितरित किए गए। अंत में मध्यरात्रि के बाद सभी प्रतिभागियों ने प्रतिज्ञा लिया।

असम के करीमगंज जिले में सामूहिक जागरण में लगभग 100 मजदूरों ने भाग लिया। 24 अन्य जिलों में 34 स्थानों पर, झंडारोहण किया गया और कार्यक्रम का उद्देश्य समझाया गया था। इन कार्यक्रमों में लगभग 5,000 लोगों ने भाग लिया।

दिल्ली में, कार्यक्रम गाजियाबाद और नोएडा में आयोजित किया गया था। महिलाओं और बच्चों ने अच्छी संख्या में भाग लिया। जनम ने एक नुक्कड़ नाटक किया। एक केंद्र में मोमबत्ती जुलूस आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम रात्रि 11.00 बजे समाप्त हुए।

गुजरात में 6 जिला मुख्यालयों में मुख्य केंद्रों में आयोजित सामूहिक जागरण में भाग लेने वाले ज्यादातर आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारी थे। 1900 की कुल भागीदारी के साथ प्रत्येक केंद्र में लगभग 200–400 ने भाग लिया। किसानों ने भी एक केंद्र में भाग लिया।

यह कार्यक्रम हरियाणा के 18 जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया था। इसके अलावा, 1 जिले में यह 15 अगस्त को आयोजित किया गया था। यह भी रिपोर्ट मिली है कि हिमाचल प्रदेश के 4–5 जिलों में किया गया था।

झारखंड में सीटू ने स्वतंत्रता के दृष्टिकोण और आज की स्थिति से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा, बहस, सेमिनार इत्यादि आयोजित करके 12 जिलों में 12 प्रमुख शहरों में आयोजित कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवियों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। स्लाइड एवं फिल्म शो, बच्चों के लिए प्रतियोगिताऐं और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। मध्यरात्रि में प्रतिज्ञा ली गई थी।

कर्नाटक के 25 जिलों में 60 केंद्रों पर सामूहिक जागरण आयोजित किया गया था। बारिश, के बावजूद भी 9190 मजदूरों ने भाग लिया। राज्य की राजधानी, बेंगलुरु और कुछ अन्य जिला मुख्यालयों में, यह पूरी रात आयोजित किया गया था। कई अन्य जगहों पर बारिश की वजह से कार्यक्रम आधी रात तक समाप्त होना था। कुछ केंद्रों में इसे इनडोर कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। बेंगलुरू में एक 102 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया गया था। शाम को भारी बारिश जिसने शहर को हिलाकर रख दिया, के बावजूद, लगभग 1500 ने भाग लिया और उनमें से ज्यादातर रात भर रहे। सभी जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

कार्यक्रमों, भाषणों आदि के साथ पूरी रात जागरण मध्यप्रदेश में 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था जबकि 3 अन्य जिलों में मध्यरात्रि तक अच्छी तरह से मनाया गया था।

600 से 1500 मजदूरों ने प्रत्येक 6 केंद्रों में भाग लिया, जहाँ से महाराश्ट्र के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर 5000 से ज्यादा ने भाग लिया। मजदूरों ने उत्साहपूर्वक जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। इसने मजदूरों की विभिन्न प्रतिभाओं को उभारने का अवसर बनाया है। परिवार के सदस्यों और बच्चों ने भी कई जगहों पर भाग लिया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। आम तौर पर आम जनता द्वारा इसकी सराहना की गयी थी।

ओडिशा के राउरकेला और पारादीप में रात भर अलग–अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सामूहिक जागरण 11 से अधिक जिलों में आयोजित किया गया था। राउरकेला में, 'अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए, मैं राष्ट्र के लिए दौडूंगा' के नारे के साथ मैराथन; प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिताओं, बहस, सेमिनार, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, खेल और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पंजाब के 10 जिलों में 15 से अधिक केंद्रों पर डोल बजाते हुए, मषाल जुलूस और मोमबत्ती जुलूस के साथ सामूहिक जागरण आयोजित किया गया। रात में बाजारों के बन्द होने के समय तक कार्यक्रम जारी रहा। होशियारपुर में, उद्योग मंत्री के घर के सामने मोमबत्ती जुलूस और जागरण आयोजित किया गया। गांव चौकीदार और परिवहन मजदूरों ने टिन के बक्से पीटने और 100 गांवों में बैठकों का आयोजन किया।

राजस्थान में, रात भर के लिए जागरध कम से कम एक जिले में आयोजित किया गया जबकि 15 अन्य जगहों पर मध्यरात्रि तक मनाया गया था। एक अन्य जिले में यह 15 अगस्त को मनाया गया था।

8096 मजदूरों और 3216 किसानों सहित अन्य लोगों, खेत मजदूरों, महिलाओं और छात्रों सहित ने तेलंगाना में कार्यक्रम में भाग लिया, जो राज्य के कुल 32 जिलों में से 29 में 140 केंद्रों में आयोजित किया गया था।

उत्तराखंड में, जागरण 4–5 जिला केंद्रों में आयोजित किया गया था जिसमें सैकड़ों मजदूरों और कुछ किसानों ने भी भाग लिया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

पष्चिम बंगाल में इस कार्यक्रम में बहुत उत्साह और इसे व्यापक सराहना मिली। कोलकाता में 12 जिलों के करीब 1600 मजदूर एकत्रित हुए और रात भर जागते रहे। यह 4 अन्य केंद्रों में भी आयोजित किया गया जिसमें प्रत्येक केन्द्र पर 700–4000 मजदूरों की भागीदारी रही थी। सभी केंद्रों में कार्यक्रम षाम से सुबह तक आयोजित किया गया था। सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेल के मैदान और पेशेवरों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। दार्जिलिंग में आयोजित कार्यक्रम में चाय बागान मजदूरों के संघर्ष के वृत्तचित्र प्रस्तुत किए गए। मालदा में कार्यक्रम का पूरा खर्च जनता द्वारा किया गया; उन्होंने प्रतिभागियों को भोजन भी प्रदान किया।

कुल मिलाकर सामूहिक जागरण के अभिनव कार्यक्रम स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले आम लोगों के दृष्टि की ओर युवा मजदूरों के ध्यान को आकर्शित करने में सफल रहा, और उनके सपनों को साकार करने के लिए आज लड़ाई जारी रखने की आवश्यकता है।

मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

28 सितम्बर 2018; मावलंकर हॉल, नई दिल्ली

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने नई दिल्ली में अपनी 21 जुलाई 2018 की बैठक में 28 सितंबर 2018 को 10.30 बजे से नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में, मजदूरों की आम माँगों के अनुसरण के लिए दो दिन की हड़ताल सहित कार्यवाही का कार्यक्रम तैयार करने के लिए, मजदूरों का एक संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया।

सीटू के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी; और राज्य समितियों और उद्योगवार फैडरेशनों के प्रतिनिधिमंडल, 8 अगस्त, 2018 के सीटू के परिपत्र में निर्धारित कोटा के अनुसार इसमें भाग लेंगे।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त वक्तव्य

4 अगस्त, 2018

प्रिय मित्रो,

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने 21 जुलाई 2018 को हुई मीटिंग में यह गम्भीरता से नोट किया है कि एन.डी.ए. सरकार मजदूर अधिकारों के खिलाफ लगातार और आक्रामक कदम उठा रही है, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के दृष्टिकोण/सुझावों को नजरअन्दाज करते हुए विभिन्न संहिताओं (कोडस्), फिक्स टर्म एम्पलॉयमैन्ट को एक नीति के तौर पर लाना आदि, को आगे बढ़ा रही है।

इस पृष्ठभूमि में अपने संघर्षों को संयुक्त रुप से तेज करने का निर्णय लिया गया है। कार्रवाहियों का कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय हुआ है, और राज्य स्तर पर सम्मेलनों (जहाँ संभव हो जिला स्तर पर भी), क्षेत्रीय राष्ट्रीय और किसी अन्य रुप में सम्मेलनों को आयोजित करने की समय सारिणी तैयार की जा सके ताकि इस वर्ष के अंत में दो दिवसीय हड़ताल करने की तैयारियां करने के लिए आगे बढ़ा जा सके।

सम्मेलन 28 सितम्बर को प्रातः 10.30 बजे से मावलंकर हॉल में आयोजित किया जाएगा।

सम्बन्धित यूनियनों का प्रतिनिधित्व विचार विमर्श के बाद तय किया जाएगा और तदनुसार बाद में सभी को सूचित किया जाएगा।

INTUC	AITUC	HMS	CITU	AIUTUC
TUCC	SEWA	AICCTU	LPF	UTUC

शताब्दी की विनाशकारी बाढ़

विजयी होकर निकलेगा केरल

ए के पद्मनाभन, उपाध्यक्ष,सीटू

'अभूतपूर्व विनाश' या कोई अन्य शब्द केरल में अगस्त के तीन सप्ताह तक जो हुआ उसे बताने के लिए काफी नहीं है। पिछले 94 वर्षों में वहाँ आयी यह सबसे भयंकर बाढ़ थी। लेकिन, इतने वर्षों में आये भौतिक बदलावों व निर्माण के मद्देनजर इसकी तुलना नहीं की जा सकती। यह कोई सीमित इलाके में आयी विपदा नहीं थी। राज्य के लगभग हर हिस्से को प्रकृति के रौद्ररुप का सामना करना पड़ा। बाढ़ इतनी विकराल थी कि बहुमंजिली इमारतों की पहली मंजिले पूरी तरह पानी में डूब गई। फसलें, बागान,दुकानें व व्यापार सब चौपट हो गया –भारी नुकसान हुआ।

मुख्यमंत्री पिन्नरायी विजयन के परोक्ष नेतृत्व में, राज्य सरकार की मशीनरी ने स्थिति की गंभीरता के अनुरुप आगे बढ़कर चुनौती का सामना किया; और सैन्य बलों व राष्ट्रीय आपदा राहत बल समय पर की गई मदद व लोगों के सक्रिय समर्थन के बल पर चुनौतियों का मुकाबला किया गया। केरल की जनता संकट के सामने एक विशाल ताकत के रुप में डट कर खड़ी हो गयी। उन्होंने आपदा का मुकाबला किया और समर्पित वालांटियरों ने हजारों लोगों व पशुओं को बचाया। लगभग 15 लाख लोगों ने सरकार द्वारा संचालित किये गये शिविरों में शरण ली जिनकी देख–रेख का जिम्मा हजारों की संख्या में वालंटियरों के रुप में काम करने वाले पुरुषों–महिलाओं व स्कूली बच्चों ने संभाला। बचाव कार्यों में लगे इन वालंटियरों में सबसे उल्लेखनीय भूमिका मछुआरों ने निभायी जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी नावें लेकर केरल के बाढ़ में डूबे अंदरुनी हिस्सों में पहुँचे और त्याग की नई मिशाल कायम करते हुए लगभग 75000 लोगों की जान बचायी।

बचाव अभियानों के दौरान व उसके बाद आयी रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि शिविरों में लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं रहने दी गयी। यहाँ तक कि यूनिसेफ के उन अधिकारियों ने जिन्होंने शिविरों का दौरा किया कहा कि इन शिविरों का प्रबंध ान बहुत ही उच्च व सुरक्षित स्थितियों में किया गया।

ऐसा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के सभी हिस्सों तथा विदेशों से भी मिले भारी समर्थन व एकजुटता के कारण संभव हुआ। धन व सामग्री बड़े पैमाने पर पहुँचाई गई। जनता के विभिन्न तबकों की भागेदारी अभूतपूर्व थी। छोटे–छोटे बच्चों द्वारा अपनी गुल्लकों और अनाथलयों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों द्वारा योगदान के लिए आगे आने के साथ ही समाज के जितने तबके अपने योगदान व एकजुटता के माध्यम से केरल की मदद के लिए आगे आये उनकी गिनती कर पाना मुश्किल है!

पानी के स्तर के घटने से साथ ही बचाव का काम पूरा हो गया है। अब राहत और पुनर्निर्माण का समय है। केरल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब लक्ष्य नये केरल के निर्माण का है।

भारत सरकार ने फौरी मदद के रुप में 600 करोड़ रुपये दिये। मुख्यमंत्री राहत कोष में 30 अगस्त तक 1027 करोड़ रुपये जमा हो चुके थे। भारी मात्रा में राहत सामग्री राहत शिविरों में पहुँची। केरल ही नहीं अन्य राज्यों से भी,विशेषकर पड़ौसी राज्यों जैसे तमिलनाडु से मजदूरों,कर्मचारियों,अधिकारियों व अन्य ने बढ़–चढ़ कर पैसे व सामग्री की मदद दी। केरल में व तमिलनाडु में विशेषकर सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों व परिवहन तथा बिजली आदि केन्द्रीय व सार्वजनिक उपक्रमों ने क्रमशः 2 दिन व 3 दिन का वेतन देने की पेशकश की। सीटू के आह्वान पर उसकी यूनियनों ने राहत जुटाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया।

एक महीने के वेतन का आह्वान

केरल के मुख्यमंत्री ने केरल व उसके बाहर रहने वाले केरलवासियों से एक महीने का वेतन राहत के लिए देने का आह्वान किया है,जिसे 10 किस्तों में दिया जा सकता है, जिसका प्रत्युत्र उत्साहवर्धक है। सीटू की केरल राज्य समिति ने सभी मजदूरों व कर्मचारियों से एक महीने का वेतन देने की अपील की है।

मुख्यमंत्री पिन्नरायी विजयन के नेतृत्व में प्रशासन ने और केरल की जनता ने जिस प्रकार से चुनौती का सामना किया है उसने देश –विदेश में मीडिया,बुद्धिजीवियों व कार्यकर्ताओं का ध्यान आकृष्ट किया है। इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए केरल की जनता की एकता और भी मजबूत हुई है। जैसा कि मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, '' लोगों के एकजुट प्रयासों से केरल विजयी होकर निकलेगा।'' हम जानते हैं कि चुनौतियाँ बहुत घनी व बड़ी हैं,लेकिन एकजुट लोग उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम कामयाब होंगे।

मानसून का कहर और नुकसान

आमतौर पर मानसून की शुरुआत 1 जून से होती है। इस वर्ष 1 जून से लेकर जुलाई के अंत तक 15 प्रतिशत अधिक बारिश हुई थी और 1 से 8 अगस्त के बीच यह 35 प्रतिशत कम थी। इसके बाद 8 अगस्त से 16 अगस्त तक हुई चक्रवाती तूफानी बारिश,सामान्यतः होने वाली बारिश से 362 प्रतिशत अधिक हो गई। इडुक्की में तो यह 568 प्रतिशत ज्यादा थी।

इस भीषण बाढ़ में 483 लोगों की मृत्यु हो गई; 14 लोग लापता हो गये; 140 लोगों को अस्पतालों में दाखिल कराया गया तथा 21 अगस्त तक 14,50,707 लोग राहत शिविरों में थे। 30 अगस्त तक भी 16,767 परिवारों के 59,296 लोग शिविरों में थे।

57,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई। सभी सड़कें,पुल,रास्तों, को क्षति पहुँची है। कोचीन हवाई अड्डा 15 दिन तक बंद रहा। वास्तविक कुल नुकसान का अभी भी आकलन किया जा रहा है।

केरल में बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए

फंड और सामग्री एकत्र करने के लिए सीटू का तात्कालिक आह्वान्

सीटू ने अपनी इकाइयों, यूनियनों, फेडरेशनों और देश भर में बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग का आह्वान किया है कि केरल में एक सदी की विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल धन और सामग्रियों को एकत्र करने में जुट जाऐं। वहाँ भू–स्खलन; मौतें लगातार बढ़ रही हैं और लोग गायब हैं; घरों को भारी नुकसान और बर्बाद हुए हैं। खेती और वृक्षारोपण नष्ट हुआ है; लाखों लोग राहत षिविरों में आश्रय लिए हुए हैं; सभी सड़क, रेल और वायुमार्गों को बर्बाद कर दिया है; अनुमानित नुकसान 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ है।

पानी कम होने के साथ ही पुनर्वास और नए निर्माण के बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों और वर्गीय, जन एवं सामाजिक संगठनों तथा स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करते हुए एलडीएफ सरकार प्रशंसनीय काम कर रही है;। बाढ़ राहत के लिए सीटू केंद्र ने केरल राज्य समिति को 1 लाख रुपय पहुंचाए हैं।

बेरोजगारी और कमजोर अस्थाई रोजगार : आई एल ओ

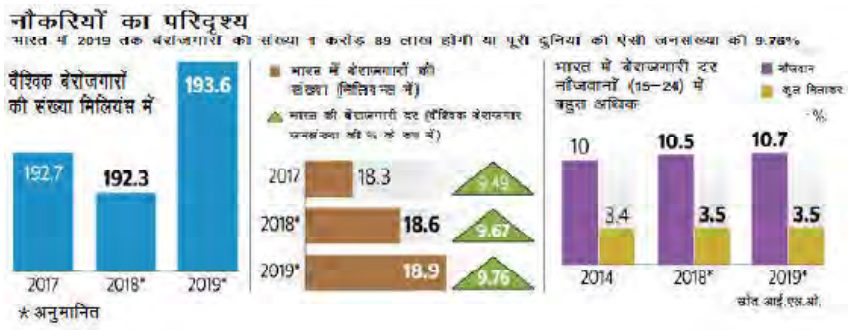

¼lkHkkj% ykbo fe‚V] 24 tuojh] 2018½

77% मजदूर कमजोर अस्थाई रोजगार में

- **vkbZ,yvks dh fo'o jkstxkj vkSj lkektd fjikVZ 2018 ds vuqlkj Hkkjr esa 77% etnwjksa dks 2019 rd detksj jkstxkj feyxkA**
- **Hkkjr esa detksj jkstxkj dk Lrj nfu;k ;k nf{k.k ,f'k;k {ks= dh rqyuk esa vf/kd gSA 2019 esa Hkkjr esa 53-5 djksM+ Je 'kfDr esa lsa dsoy 39-86 djksM+ dks ?kfV;k xq.koÙkk okyh ukSdfj;k gkSxhA**

(कमजोर रोजगार का निर्धारण अपर्याप्त कमाई, कम उत्पादकता और काम की मुश्किल परिस्थितियों की विशेषता से होता है जो मजदूरों के मालिक अधिकारों को क्षीण करते हैं। वे अनौपचारिक रूप से नियोजित हैं। नौकरियों की खराब गुणवत्ता और उच्च अनौपचारिकता, आईएलओ ने कहा है कि ''कामकाजी गरीबों'' के तय होने में महत्वपूर्ण बिन्दु है कि जो प्रति दिन 198 रुपये से कम की आय पर गुजारा करने वाले लोग हैं।)

(साभार: लाइव मिन्ट, 24 जनवरी 2018)

उद्योग व क्षेत्र

सड़क परिवहन

मोटर वाहन संशोधन विधेयक के खिलाफ

परिवहन मजदूरों की विशाल राष्ट्रव्यापी हड़ताल

सभी सैक्टरों में अनुमानित तीन करोड़ से ज्यादा सड़क परिवहन मजदूरों ने संसद में लम्बित क्रूर मोटर वाहन संशोधन विधेयक के विरोध में और अपनी प्रमुख माँगों को लेकर शानदार देशव्यापी हड़ताल की। सीटू ने 7 अगस्त को जारी एक बयान में कहा कि इस इस विधेयक को राज्य परिवहन निगमों को तहस–नहस कर देने, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पूरी तरह से निजीकरण करने की प्रक्रिया को तेज करने और उसे कॉरपोरेटों द्वारा कब्जा लेने के बाद उस पर एकाधिकार और सार्वजनिक परिवहन के किरायों में वृद्धि करने के लिए तैयार किया गया है। ऐसा होना आम मेहनतकश लोगों के विरुद्ध होगा। विधोयक से छोटे ट्रान्सपोर्टरों समेत सार्वजनिक व माल परिवहन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मजदूरों को रोजगार छिन जाएगा। यह हड़ताल लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन को लगातार मंहगा बनाने वाली डीजल–पेट्रोल की बार–बार बढ़ती कीमतों के भी विरुद्ध थी।

सीटू ने इस विशाल संयुक्त देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाई के लिए सड़क परिवहन मजदूरों को बधाई दी और मोदी सरकार से माँग की कि वह इस देशव्यापी विरोध के मद्देनजर संसद में लंबित मोटर वाहन संशोधन विधेयक को वापस ले।

राजस्थान में राज्य सड़क परिवहन मजदूरों की 2 दिन की हड़ताल, समझौता

सीटू, एटक, इंटक, बी.जे.एम.एम. की यूनियनों और दो सेवानिवष्त कर्मचारियों की एसोसिएशनों के संयुक्त मंच के नेतृत्व में; राजस्थान सड़क परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.) के 17,000 से अधिक कर्मचारी अपने 13 सूत्रीय माँग पत्र को लेकर 24 जुलाई की मध्य रात्रि से लेकर 26 जुलाई की मध्य रात्रि तक के लिए 48 घंटे की राज्यव्यापी मुकम्मल हड़ताल पर चले गए और आर.एस.आर.टी.सी. की राज्य एवं लम्बी दूरी की अंर्तराज्यीय रुटों की 4,800 बसों को डिपुओं में पूरी तरह अचलनीय बनाकर खड़ा कर दिया; आर.एस.आर.टी.सी. बसों द्वारा रोजाना यात्रा करने वाले 5 लाख लोग फँस गए और आर.एस.आर.टी.सी. को दो दिनों में टिकट बिक्री से होने वाली 10 करोड़ रुपये की आमदनी की हानि हुई। बीएमएस यूनियन ने संयुक्त मोर्चे और हड़ताल से खुद को दूर रखा।

सफल हड़ताल के बाद सरकार और प्रबंधन को स्पष्ट संदेश देने के बाद, संयुक्त मोर्चे की यूनियनों, आर.एस.आर.टी.सी. प्रबंधन और राज्य सरकार की एक त्रिपक्षीय बैठक अगले ही दिन 27 जुलाई को राज्य के परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई और उसी दिन एक लिखित समझौता हुआ। इस समझौते में राज्य सरकार आर.एस.आर.टी.सी. को तत्काल 150 करोड़ रुपये का योगदान देगी, जिसमें से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके बकाए के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और कर्मचारियों को भत्ते के रूप में 50 करोड़ रूपए दिए जाऐंगे; परिवहन मंत्री और आर.एस.आर.टी.सी. प्रबंधन ने अचलनीय बसों को चरणबद्ध तरीके से बदलने का आश्वासन दिया; राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन और रिक्त पदों को भरने के लिए, कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों सहित एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो इन माँगों के कार्यान्वयन पर 31 अगस्त, 2018 के भीतर सरकार को रिपोर्ट जमा करेगी।

पंजाब में सड़क परिवहन ठेका मजदूरों की 3 दिन की हड़ताल

सीटू से संबधित पनबस कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन के नेतष्त्व में, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब रोडवेज के लगभग 5,000 ठेका मजदूर इसके सभी 18 डिपो और 2 उप–डिपो में 16–18 जुलाई को 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल पर थे। स्थानीय बसों का चलना बन्द हो गया और पंजाब रोडवेज की सभी 1,800 बसें डिपो में फंस गयी, राज्य के विभिन्न हिस्सों से प्रेस को सूचना मिली। हड़ताली श्रमिकों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बस डिपो के सामने रैलियों, प्रदर्शन और गेट मीटिंग आयोजित की। 17 जुलाई को राज्य परिवहन मंत्री के दीना नगर विधानसभा क्षेत्र में जुझारु रैली और प्रदर्शन आयोजित किया गया। जब सरकार ने उनकी लंबी लंबित माँगों पर चर्चा के लिए 26 जुलाई को यूनियन और राज्य के परिवहन मंत्री के बीच बैठक तय की है।

तमिलनाडू में पेट्रोल डीजल की मूल्यवृद्धि के खिलाफ ऑटो मजदूरों का प्रदर्शन

ऑटो वर्कर्स फेडरेशन और सीटू राज्य समिति के आह्वान पर, लगभग 5,100 ऑटो मजदूरों ने 21 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कलेक्टरों और आरटीओ कार्यालयों के सामने राज्यव्यापी प्रदर्शनों का आयोजन किया।

योजना मजदूर

10 जुलाई माँग दिवस में लाखों आंगनवाड़ी कर्मी शामिल हुए

सीटू से संबद्ध आंगनवाड़ी कर्मचारियों के फेडरेशन ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के आह्वान पर, लाखों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी आदि 24 राज्यों में जिला प्रशासन कार्यालयों के समक्ष 'आईसीडीएस बचाने, विघटन के खिलाफ' नारे के साथ प्रदर्शन करके 10 जुलाई को और ओडिशा में 9 जुलाई को और दिल्ली में 20 जुलाई को अखिल भारतीय माँग दिवस मनाया। प्रधान मंत्री को संबोधित ज्ञापन, जिसमें आईसीडीएस को खत्म करने की मोदी सरकार की चाल के खिलाफ, और 3 बिंदुओं की माँगों के लिए जिला प्रशासन को प्रस्तुत किया गया था। विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों और केंद्रीय मंत्रियों के सामने उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन भी आयोजित किए गए थे।

सरकार के आईसीडीएस को विघटित करने के कदमों में, पूरक पोषण के स्थान पर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की शुरूआत शामिल है; आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थान पर नर्सरी स्कूल खोलना; और आंगनवाड़ी केंद्रों को कॉरपोरेटों और कॉरपोरेटी गैर सरकारी संगठनों को सौंपना है। माँगों में 1) आईसीडीएस सेवाओं के लिए अनिवार्य आधार संबंध के खिलाफ और किसी भी रूप में आईसीडीएस के निजीकरण को रोकने के लिए, आईसीडीएस में सीधे/सशर्त नकदी हस्तांतरण और पैक किए गए भोजन को शुरू करने के कदम को तुरंत रोका जाए; 2) आईसीडीएस को सार्वभौमिक बनाने और संस्थागत करने, आईसीडीएस की बजट कटौती की वापसी हो और केंद्रीय बजट में आईसीडीएस के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने के लिए; और 3) आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायकों को 'मजदूर' के रूप में पहचानने के लिए 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने के लिए, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान 18000 रुपये से कम न हो और प्रति माह 3000 रुपये से कम पेंशन नहीं सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने आदि शामिल हैं।

ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. ने प्रधान मंत्री को संबोधित इन माँगों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया। लगभग 3 करोड़ हस्ताक्षर प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के आह्वान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया सांप्रदायिक नवउदारवादी सरकार के खिलाफ मजदूर वर्ग के बीच गुस्से को दर्शाती है।

कुपोषण, निरक्षरता और बीमार स्वास्थ्य से आजादी'' के नारे के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक 9 अगस्त को 'जेल भरो' आंदोलन में; और 14 अगस्त को सामूहिक जागरण में शामिल होंगे; और दिल्ली में 5 सितंबर के मजदूर किसान संघर्ष रैली में 50,000 की विशाल लामबन्दी के साथ शामिल होगें।

बीएमएस और इसके आंगनवाड़ी फेडरेशन ने भी 10 जुलाई को जिला प्रदर्शनों का आह्वान किया। हालांकि, आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने इसे उसके विभाजनकारी और विघटनवादी कदम के रूप में ही लिया। जैसा कि उसने 2 सितंबर 2015 की संयुक्त अखिल भारतीय आम हड़ताल जिसके आह्वान में शामिल होने के बाद 2 दिन पहले इससे बाहर होने और उनके आंगनवाड़ी फेडरेशन ने, 9–11 नवंबर को होने वाले मजदूरों के संयुक्त महापड़ाव से एक सप्ताह पहले दिल्ली चलो का कार्यक्रम करके अपना विश्वासघात जाहिर किया था।

सीमेंट

द्विपक्षीय वार्ता

सीमेंट उद्योग में पिछले वेतन समझौते की अवधि पूरी हो जाने पर सीमेंट मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी एम ए) तथा 6 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों – सीटू, इंटक, एटक, बी एम एस, एच एम एस व एल पी एफ की सीमेंट मजदूरों की यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच 27 अगस्त को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय वेतन वार्ता हुई। इसमें सीटू का प्रतिनिधित्व निसीथ चौधरी (सीमेंट उद्योग में नई बनी सीटू की राष्ट्रीय समन्वय समिति के संयोजक), तमिलनाडू से प्रकाश कुमार तथा राजस्थान से कालू राम सुथार ने किया। बैठक में सभी 6 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि तथा नियोक्ताओं की ओर से तीन प्रतिनिधियों को शामिल कर एक छोटी समिति गठित की गयी। तथापि किसी के उपस्थित न हो पाने की स्थिति में संबंधित संगठन से कोई अन्य प्रतिनिधि के रुप में जगह ले सकेगा। यह छोटी समिति अपने विचार–विमर्श को पूर्ण वार्ता समिति के सामने रखेगी जो अंतिम निर्णय लेगी। छोटी समिति की पहली बैठक 7 सितम्बर को चेन्नई में होनी तय हुई है।

राज्यों से

if'pe cxky

चाय बागान मजदूरों की 3 दिन की अभूतपूर्व हड़ताल

चाय बागानों के सामने हड़ताली मजदूर

(बाएं से) 1. अलीपुरद्वार; 2. तराई में ओराड; 3. सीटू चाय वर्कर्स यूनियन के नेता सामन पाठक मिरिक घाटी में हड़ताली मजदूरों को संबोधित करते हुए (सौजन्यः गणशक्ति)

सभी 26 चाय ट्रेड यूनियनों के चाय बागान मजदूरों के संयुक्त फोरम के बैनर के तहत 7–9 अगस्त को चाय मजदूरों की 3 दिनों की एकजुट हड़ताल के साथ, इस संयुक्त मंच के आह्वान को यूनियनों की संबद्धता से उठकर और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स, तराई और द्वार के तीन चाय उत्पादक क्षेत्रों में व्यापक प्रतिक्रिया के साथ, चल रहे आंदोलन ने एक नए चरण में प्रवेश किया। न्यूनतम मजदूरी तय करने की माँग मुख्य है जो साढ़े तीन वर्शों से संशोधन के लिए लंबित है।

सीटू के प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन के नेता और संयुक्त फोरम के संयोजकों में से एक, जियाउल आलम ने कहा कि आज मजदूर कम वेतन के वेतन समझौते के बजाय, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत न्यूनतम वेतन की माँग कर रहे हैं।

चाय बागानों में लंबे सेमय से न्यूनतम वेतन की माँग को लेकर, चाय उद्योग में तीन दिन की हड़ताल, जिसे 26 चाय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त फोरम द्वारा बुलाया गया था, मंगलवार को अपने पहले दिन शुरु हुई। 8 अगस्त, 2018 को बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का भी गठन किया था, जिसमें कई बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

पश्चिम बंगाल राज्य के हिमालय की तलहटी में 370 बागानों में 4,00,000 से अधिक चाय मजदूरों ने सुरम्य दार्जिलिंग पहाड़ी स्टेशन के नजदीक के क्षेत्र में अधिकांश चाय बागानों में काम बंद कर दिया, ब्रिटेन के समाचार पत्र द गार्जियन ने 7 अगस्त को फ्रांसीसी समाचार एजेंसी एजेंस फ्रांस प्रेस का हवाला दिया है कि ''ब्रिटिश शासित भारत के अवशेष, पूर्व और उत्तर–पूर्व हिस्सों में चाय बागान में मजदूरी विवादों और मजदूरों के काम करने की खराब स्थितियों पर राष्ट्रीय शीर्षक बनते हैं।''

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ''टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएआई) ने कहा, ''इस हड़ताल के परिणामस्वरूप उद्योग को 38–40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।''

7 अगस्त को अखिल भारतीय केंद्र के एक बयान में, सीटू ने पष्चिम बंगाल में 4 लाख चाय बागान मजदूरों के वीरतापूर्ण संघर्ष को बधाई दी और संघर्ष से मजदूरों की शानदार एकता ने राज्य सरकार से बढ़ी न्यूनतम मजदूरी को अधिसूचित करने की मांग की है, जो लंबे समय से लंबित है और टीएमसी सरकार ने संयुक्त फोरम से वादा

किया था। सीटू ने अन्य मजदूरों और यूनियनों को चाय बागान मजदूरों के निरंतर संघर्षों को समर्थन और एकजुटता को बढ़ाने के लिए कहा है। भारी हड़ताल में टी एम सी यूनियन से जुड़े मजदूर भी शामिल हुए जबकि उनके नेता राज्य प्रशासन के साथ घूम रहे थें।

चाय मजदूरों के वेज रिवीजन डिमांड फोरम के तहत 30 लाख चाय मजदूरों में उथल–पुथल है और उन्होने पडोसी राज्य असम के 800 चाय बागानों में विरोध रैलियां निकाली। वे अपने न्यूनतम वेतन 137 रुपयें को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन के तहत न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं।

हरियाणा

निर्माण मजदूरों की आक्रोष रैली

समूचे हरियाणा से आये हजारों निर्माण मजदूर 11 जुलाई को पंचकूला में राज्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड के कार्यालय के बाहर सीटू की भवन निर्माण कामगार यूनियन की आक्रोश रैली में शामिल हुए और अपनी माँगों को लेकर तथा अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के विरोध में घंटो तक घेरा डाला। आक्रोश रैली से पूर्व दो राज्य स्तरीय जत्थे निकाले गये जिन्होने राज्य के अलग–अगल भागों में निर्माण मजदूरों की 100 से अधिक सभाओं को संबोधित किया।

रैली को सीटू के राज्याध्यक्ष सतबीर सिंह; सी.पी.आई.(एम.) के राज्य सचिव सुरेन्द्र मलिक; यूनियन के नेताओं – महासचिव सुखवीर सिंह, अध्यक्ष देशराज, कोषाध्यक्ष राम मेहर सिंह व अन्य; तथा खेत मजदूर यूनियन, किसान सभा व एडवा के राज्य नेताओं ने संबोधित किया।

अपने संबोधनों में नेताओं ने निर्माण मजदूरों के पंजीकरण व राज्य निर्माण मजदूर कल्याण कोष से उन्हे मिलने वाले लाभों से जुड़ी उनकी माँगें; तथा भाजपा शासित राज्यों में फंड व उसके प्रशासन से जुड़े भ्रष्टाचार, दुरुपयोग व अनियमिताओं को उठाया।

इनमें निर्माण मजदूरों के ऑफ लाइन पंजीकरण की माँग, समय पर लाभ सुनिश्चित करने, सभी जिलों में बोर्ड के कार्यालय खोलने, तथा ऑन लाइन पंजीकरण व उसके दुरुपयोग को रोकने, राजनैतिक प्रचार व लाभ के लिए गैर नियोजित खर्चों जैसे ढ़ेरों सिलाई मशीनों का कैम्प आयोजित कर वितरण करने तथा दुरुपयोग रोगने, जिलों में आधारभूत ढ़ाँचे का निर्माण न होने तथा सरकारी स्टाफ की नियुक्ति न होने, मृत्यु होने पर दिये जाने वाले मुआवजों का वर्षों से लंबित रहना; चिकित्सीय इलाज व आवास के लिए भुगतान न होने, 22 घोषित फायदों के बदले केवल 14 लाभों का उनलब्ध होना; 2900 करोड़ रुपयें के संचयित फंड को शेयर बाजार में अवैध रुप से लगाने; पंजीकरण और लाभ की उपलब्धता आदि में जिलावार असमानता और विभिन्नता है। सरकार ने बोर्ड में बीएमएस प्रतिनिधियों की राजनीतिक नियुक्ति की है, सीटू और अन्य यूनिययनों के खिलाफ भेदभाव किया है; और सलाहकार समिति में भाजपा नेता हैं। उनमें से किसी का भी निर्माण मजदूरों से कोई संबंध नहीं है।

सीटू और यूनियन लगातार इन माँगों और मुद्दों को उठा रहे हैं; मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री तक पहुंचे और मजदूर प्रतिनिधिमंडल चर्चा की गयी है। फिर भी, सरकार द्वारा कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाया जिसने उन्हें इस आक्रोष रैली को करने के लिए मजबूर किया है।

श्रम आयुक्त और श्रम मंत्री से परामर्श करने के बाद, बोर्ड के संयुक्त निदेशक से लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त करने के बाद, आक्रोश रैली समाप्त हुई। उठायी गयी माँगों और मुद्दों पर विचार करने के लिए, यूनियन और श्रम मंत्री के बीच 17 जुलाई की बैठक तय हुई। (द्वारा: राममेहर सिंह)

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkbl

jkT;	dn	tu 2018	tykbl 2018
vk/k inz'k	x.Vj	280	284
	gnjkckn	278	284
	fo'kk[kkiÿkue	284	288
	okjxy	264	270
vle	MeMek frulf[k;k	251	259
	xokgkVh	261	264
	ycd flYpj	249	252
	efj;kuh tkjgkV	246	249
	jxkikjk rtij	306	320
fcgkj	e?kj&tekyiqj	293	302
p.Mhx<	p.Mhx<	318	322
NÿkhlX<	fHkykbl	265	283
fnYyh	fnYyh	319	332
Xkkvk	xkvk	269	274
Xktjkr	vgenkckn Hkkouxj	272	287
	jktdkV	280	290
	lqjr	264	265
	oMknjk gfj;k.kk	26	272
Qjhnkckn		264	274
	;euk uxj	277	287
fgekpy	fgekpy çn'k	258	265
tEe ,oa d'ehj	Jhuxj	269	272
>kj[k.M	ckdkjk	288	294
	fxfjMhg	315	330
	te'kniqj	338	346
	>fj;k	325	340
	dkMek	338	361
	jkph gfV;k	337	360
dukVd	cyxke	298	298
	cxykj	288	290
	gcyh /kkjokM	312	317
	ejdjk	302	303
	eqjj	302	304
djy	,.kkdlye@vyobl	308	310
	e.MkD;ke	309	309
	fDoyku	342	348
e/; çn'k	Hkkiky	293	313
	fNnokMk	290	296
	bnkj	266	274
	tcyiqj	291	306

jkT;	dn	tu 2018	tykbl 2018
महाराष्ट्र	मुम्बई	293	298
	ukxiqj	329	361
	ukfld	307	335
	iq.kk	300	317
	'kkykiqj	301	310
mMhlk	vkxjy&rkypj	303	315
	jkmjdqyk	307	310
ikfMpfj	ikfMpfj	309	311
iatkc	verlj	298	319
	tkyU/kj	291	304
	yqf/k;kuk	281	286
jktLFkku	vtej	268	279
	HkhyokMk	278	280
	t;iqj	277	289
rfeyukMq	pUuk	268	269
	dk;EcVj	279	277
	dUuqj	298	315
	enjkbl	281	283
	lqye	281	284
	fr#fpjkiYyh	289	290
rqyxkuk	xknkojh[kkuh	298	310
	gnjkckn	250	253
	okjxy	300	311
f=ijk	f=ijk	266	267
mÿkj çn'k	vkxjk	320	346
	xkft;kckn	292	318
	dkuiqj	303	326
	y[kuÅ	294	320
	okjk.klh	293	314
if'pe cxky	vklulky	314	323
	nkftfyax	263	271
	nxkiqj	316	317
	gfYn;k	321	330
	gkoMk	280	285
	tkyikbxMh	284	286
	dkydkrk	276	282
	jkuhxat	265	279
	flyhxMh	264	272
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**291**	**301**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- एजेंसी – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- भुगतान – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- संपर्क: ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

आँगनवाड़ी फेडरेशन का 10 जुलाई माँग दिवस

(रिर्पोट पृ० २३)

असम

तेलंगाना

पंजाब

कर्नाटक

हरियाना में निर्माण मजदूरों का घेरा डालो

(रिर्पोट पृ० २५)

परिवहन मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल

(रिर्पोट पृ० २२)

तमिलनाडू के सलेम में संयुक्त विरोध

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-2020 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/09/2018)

ऐतिहासिक मजदूर किसान संघर्ष रैली

जुलूस का एक विहंगम दृश्य

Sea of Red in city as farmers rally for rights - ASIAN AGE

MAZDOOR KISAN SANGHARSH RALLY – Economic Times

Farmers, workers rally over loan waiver, wages – Financial Express

FARMERS' ANGER REACHES CAPITAL – Hindustan Times

Traffic stands still as one lakh protesters march on – Hindustan Times

Higher prices for crops, loan waivers, Swaminathan report: In sea of red, farmers seek green shoots – Indian Express

Thousands of farmers, workers paint Delhi red – The Hindu

Massive turnout at worker-peasant rally – The Hindu Buisness Line

Farmers bring protest to national capital – Times of India

अखबारों की सुर्खियां

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : **के हेमलता**